PRESS RELEASE

CONSUMER UNITY & TRUST SOCIETY - A registered, recognised, non-partisan, non-profit and non-government organisation pursuing social justice and economic equity within and across borders

'इनसाईट इन्टू इंडियन स्टेट्स' परियोजना का राजस्थान में शुभारम्भ

जयपुर, 12 दिसम्बर, 2013।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुबीर कुमार, मिशन डाइरेक्टर, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद् ने 'इनसाईट इन टू इंडियन स्टेट्स' परियोजना के अंदर ग्रामीण गैर– कृषि आजीविका की विवेचना करने जा रहा है। जो कि एक सराहनीय कदम है। सरकार द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम व योजनाएं चलाई जाती है, जो कि कई कारणों से परिणाम नहीं दे पाती है। सकारात्मक आलोचनाओं के द्वारा इन कार्यक्रमों में सुधार किये जा सकते हैं। इस तरह के अध्ययन के सुझाव स्पष्ट होने चाहिए ताकि सुधार के सही कदम उठाये जा सकें। श्री सुबीर कुमार 'कट्स' द्वारा आयोजित 'इनसाईट इन टू इंडियन स्टेट्स' परियोजना की आज होटल जयपुर पैलेस, जयपुर में आज 12 दिसमबर को शुभारम्भ बैठक में बोल रहे थें।

'कट्स' इन्टरनेशनल, यू.एन.डी.पी. के साथ मिलकर 'इनसाईट इन टू इंडियन स्टेट्स' नाम की एक परियोजना का राष्ट्रीय स्तर पर संचालन कर रहा है। परियोजना के अन्तर्गत चयनित चार राज्यों, असम, ओड़ीशा, कर्नाटक और राजस्थान में ग्रामीण गैर– कृषि आजीविका के क्षेत्र में सफल योजनाओं का अध्ययन किया जाएगा।

'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि ग्रामीण गैर– कृषि आजीविका के अन्तर्गत एक तिहाई लोग कार्य करते हैं जबकि इसका सकल घरेलू उत्पादन में 60 प्रतिशत हिस्सा है। अतः इस क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है। इस परियोजना के अन्तर्गत अध्ययन के निष्कर्षों को एक वेबसाइट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त वेबसाइट साधारण, उपयोग में आसान आंकड़ों एवं महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण होगी। विभिन्न राज्यों में अलग– अलग प्रतिभागी संस्थाएं परियोजना का क्रियान्वयन करेगी तथा राजस्थान में 'कट्स' इन्टरनेशनल क्रियान्वयन करेगा।

रितु माथुर, यू.एन.डी.पी. ने कहा कि आर्थिक के विकास के साथ– साथ असमानताएं बढ़ रही है। आजीविका के क्षेत्र में दक्षता में सुधार के साथ चलाए जा रहे कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग भी आवश्यक है। कार्यक्रमों का संचालन बेहतर नहीं होने पर भी उनका बजट खर्च हो जाता है। इसका एक मुख्य कारण लोगों में अधिकारों की जानकारी नहीं होना है। यह परियोजना चार राज्यों में ग्रामीण गैर– कृषि आजीविका में हो रहे प्रचलित नवाचार को

एम.एल. मेहता, पूर्व मुख्य सचिव, ने कहा कि रोजगार उत्पन्न करना सरकारों के लिए चुनौती है। हर साल लगभग दस लाख लोग इक्कीस वर्ष की आयु के हो जाते हैं, जबकि सरकार केवल तीस हजार तक को ही रोजगार उपलब्ध करा पाती है। इसलिए रोजगार के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कृषि का क्षेत्र लाभ का क्षेत्र नहीं रहा है। राजस्थान विशेष रूप से पानी की कमी के कारण ऐसी स्थिति ज्यादा है। दक्षता में सुधार एवं बाजार से जुड़ी योजनाओं को बढ़ाना आवश्यक है। सरकारों को विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है।

उक्त कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जैसे स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल डवलपमेंट, नाबार्ड, राजस्थान स्किल एण्ड लिवलीहुड डवलपमेंट कॉरपोरेशन, रूडा व अन्य गैर– कृषि आजीविका पर कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित 60 से अधिक भागीदारों से सक्रिय रूप से भाग लिया तथा विचारों का आदान– प्रदान किया।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:
अमर दीप सिंह (93146 17532)/आरती पाण्डे तिवारी
'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एकशन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट)
277, सिंधी कॉलोनी, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर– 302 016
फोनः 0141–5133259, 2282821
ईमेलः apt@cuts.org; i3s@cuts.org
वेबसाईटः http://www.cuts-international.org/cart